

These were communicated to the State Governments by the Department of Personnel and Administrative Reforms for Implementation. According to the reports received from the State Governments, necessary implemental action is being taken by them.

दामोदर बाटी परियोजना के बांधों में
भ्रष्टाचार

253. श्री स्रंकर इन्द्राज सिंह : क्या
ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर नदी बाटी परियोजना के विभिन्न बांधों में मछली पालन में सरकार को गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी धाय हुई ;

(ख) क्या मछली का व्यवसाय करने के लिए स्थानीय लोगों को सुविधाएं प्रदान की गयी थीं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या तिलैया बांध में जो स्थानीय मत्साह मछली का व्यवसाय दामोदर बाटी निगम के साथ सामंदायी में करते थे उन्हें इस सुविधा में वंचित कर दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उभरने की (श्री० किशोर्कर प्रसाद) : (क) से (ग) दामोदर बाटी निगम के जलामयों में मछली उद्योग का कार्य उक्त निगम के नियंत्रण में है और तदनुसार सरकार को इससे कोई धाय नहीं होती। दामोदर बाटी निगम द्वारा विभागीय तौर पर मछली उद्योग प्रगस्त, 1974 के मध्य से शुरू किया गया था और प्रगस्त, 1975 तक इसे जारी रखा गया। तदुपरांत मछली उद्योग का कार्य एक प्राइवेट लाइसेंस-धारी को पट्टे पर दे दिया गया है, जिससे लाइसेंस-धरक बहुत किया जा रहा है। निगम की अपने बांधों में मछली उद्योग से

पिछले तीन वर्षों में हुई धाय निम्न प्रकार की —

1973-74	शून्य
1974-75	1,07,649 रुपये
1975-76	2,36,158 रुपये

विभागीय तौर पर मछली उद्योग की प्रवृद्धि के दौरान स्थानीय मत्साहों को तथा अन्य लोगों को दामोदर बाटी निगम के जलामयों में मछली पकड़ने की अनुमति दी जाती थी, जिसके लिए उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता था परन्तु पकड़ी गई मछलियां निगम द्वारा बेची जाती थीं। वर्तमान लाइसेंसधारी को भी मत्साह दी गई है कि मछली उद्योग में स्थानीय मत्साहों को काम पर लगाएं और वह ऐसा कर रहा है।

Report of Study Group for Development of Western Ghats

254 SHRI B V NAIK Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the study group for the development of Western ghats has submitted its report;

(b) if so, what are its findings; and

(c) what the Planning Commission propose to do in regard to (b) above?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SANKAR GHOSE): (a) to (c). No study group as mentioned in (a) has been set up and (b) and (c) therefore do not arise. However, there is a high level committee which recommends various programmes to be undertaken for the development of Western Ghats region.